

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 19

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 21 जुलाई, 2025

30 आषाढ, 1947 (शक)

निजी स्वामित्व वाले विरासत गृहों के संरक्षण के लिए सहायता

19. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार देश में निजी स्वामित्व वाली धरोहरशालाओं/भवनों की कोई सूची या रजिस्ट्री रखती है और यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख): क्या ऐसी धरोहर संपत्तियों के संरक्षण, जीर्णोद्धार या अनुकूली पुनः उपयोग में निजी स्वामियों को सहायता देने के लिए कोई वित्तीय सहायता, कर प्रोत्साहन या विशेष योजनाएं मौजूद है, और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास निजी स्वामित्व वाली धरोहरशालाओं के संरक्षण के लिए वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्पित केंद्रीय योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है ?

उत्तर
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निजी स्वामित्व वाले धरोहर गृहों की कोई सूची नहीं रखता है। तथापि, भारत सरकार ने देश भर के स्मारकों और पुरावशेषों हेतु दो राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) की स्थापना की है। अभी तक, एनएमएमए ने 100 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष प्राचीन 11,406 निर्मित विरासत और स्थलों के आँकड़ों का दस्तावेजीकरण और प्रकाशन किया है। इनकी राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में संलग्न है। इन आँकड़े को एनएमएमए की वेबसाइट: <http://nmma.nic.in> पर भी डाला गया है।

(ख): संस्कृति मंत्रालय ऐसे धरोहर संपत्तियों के लिए कोई वित्तीय सहायता अथवा कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है।

(ग): इस संबंध में कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-1

लोकसभा में दिनांक 21.07.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) पर कुल निर्मित धरोहरों एवं स्थलों का राज्य वार डाला गया डेटा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल डेटा
1	आंध्र प्रदेश	1788
2	बिहार	20
3	छत्तीसगढ़	60
4	दिल्ली	872
5	गुजरात	46
6	हरियाणा	1
7	हिमाचल प्रदेश	280
8	जम्मू और कश्मीर	292
9	कर्नाटक	312
10	केरल	174
11	मध्य प्रदेश	749
12	महाराष्ट्र	32
13	ओडिशा	2015
14	पंजाब	687
15	राजस्थान	2160
16	तमिलनाडु	922
17	तेलंगाना	629
18	त्रिपुरा	4
19	उत्तर प्रदेश	228
20	पश्चिम बंगाल	135
	कुल	11406